

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
भा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

दिनांक : दिनांक : 17 जुलाई, 2007

विषय: नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर, कांगेश्वर में कंन्टीन, लिटिगेंट रोड, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा पोस्ट एवं लांकअप के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-381/टो०एच०सी०/एडमिन(बी)/निर्माण/2006, दिनांक 12.2.07 एवं पत्र संख्या-401/टो०एच०सी०/एडमिन(बी)/निर्माण/2006, दिनांक 13.2.07 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर, कांगेश्वर में कंन्टीन, लिटिगेंट रोड, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा पोस्ट एवं लांकअप के निर्माण हेतु रु० 33.28 9.78 लाख अर्थात् कुल रु० 42.86 लाख के आगणन के माध्यम टो०एच०सी० द्वारा रिटेनिंग बाल एवं फंस्ट बलि हेतु आगणित धनराशि को धराते हुए अनुमोदित रु० 30,27,000/- (तीस लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रस्ताविका एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 30,27,000/- (तीस लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) की धनराशि की व्यय किए जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहमति प्रदान करते हैं :

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से लो गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताने हेतु उपर्युक्त प्रमाण-पत्र शासन की प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाय ।
- (3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मार्गचित्र गठित कर मक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (4) कार्य पर स्वीकृत नामों के अनुसार ही व्यय किया जाय, स्वीकृत नामों से अधिक व्यय करवाया न किया जाय ।
- (5) एक मुश्त प्राविधान की कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार मक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेंकअप किया जाय ।
- (6) जी०पी०इण्डियू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई ने दण्ड वसूल किया जायेगा ।
- (7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित किया जाय ।
- (8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल-भाति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (9) आगणन में धनराशि जिन नहीं हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

- (10) निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (11) निर्माण कार्य करते समय अथवा आगमन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (12) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय तथा पूर्व में मुख्य भवन हेतु स्थल विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत हो तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितना कार्य किया गया में सम्बन्धित विस्तृत आगमन को प्रति संलग्न को जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके । आगमन के साथ विस्तृत स्थल मानचित्र संलग्न करते हुए उसमें पूर्ण दृष्टिकोण भी लाने में प्रदर्शित किया जाय ।
- रिटनिंग वाल एवं बेस्ट वाल निर्माण हेतु आगमित धनराशि को स्थल विकास में सम्मिलित करते हुए विस्तृत आगमन तैयार किया जाय । उक्त के साथ ही साथ आर०सो०सो० रिटनिंग वाल का निर्माण 1:1.5:3 के अनुपात में कराये जाने के सम्बन्ध में भूमिपूँजिता को राय भी आगमन के साथ संलग्न किया जाय ।
- (13) व्यय से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टार पब्लिशर, प्रिन्सिपल का सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विध्वक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समरूपता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (14) स्वीकृत को जा रहे धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुमान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर दृवीगत परियोजना 60-अन्य भवन 051 विभाग 00-आयोजनागत-03-स्थायिक कार्य हेतु भवने का निर्माण 24-धन निर्माण कार्य" के तहत दाखल किया जाय ।

3- यह आदेश बिल अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-704/XXVII(5)/2007, दिनांक 13.7.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भाषाई,

(आर०सो०सो०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या 4 दो(8)/XXXVI(1)(2)/2007-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, नांदरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, बगेश्वर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/टिहरी गढ़वाल ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बगेश्वर ।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
8. एन०आइ०सो०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/नार्ड फाइल ।

भाषाई से

(आलोचक कुमार शर्मा)

अवर सचिव ।